



आरत का राजपत्र

The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 227] नई विल्हेमी, शनिवार, जून 20, 1970/ज्येष्ठ 30, 1892

No. 227] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 20, 1970/JYAIKTHA 30, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह प्रालग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 20th June 1970

S.O. 2202/18A/IDRA/70.—Whereas the Central Government is of the opinion that the Rajkot Spg. & Wvg. Mills Ltd., Rajkot, an industrial undertaking in respect of which an investigation has been made under Section 15 of the Industries (Development & Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), is being managed in a manner highly detrimental to public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 18-A of the said Act, the Central Government hereby authorises the Gujarat State Textile Corporation Limited, Ahmedabad (hereinafter referred to as Authorised Controller) to take over the management of the whole of the said undertaking, namely, the Rajkot Spg. & Wvg. Mills Ltd., Rajkot, subject to the following terms and conditions, namely:—

- (i) the Authorised Controller shall comply with all directions issued from time to time by the Central Government;
- (ii) the Authorised Controller shall hold office for five years from the date of publication in the Official Gazette of this Order. The Central Government may terminate the appointment of the Authorised Controller earlier if it considers necessary to do so.

2. This Order shall have effect for a period of five years commencing on the date of its publication in the Official Gazette.

[No. F.9(8)/Lic.Pol./68.]

R. C. SETHI, Under Secy

ओद्योगिक विकास, राष्ट्रस्तरीक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्रालय

(ओद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 20 जून 1970

का० फा० 2202/18ए०/धाई० डी० फा० ए०/70.—यतः केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि दि राजकोट स्पर्धनग एण्ड बीविंग मिल्स लि०, राजकोट नामक एक ओद्योगिक उपक्रम का, जिसके सम्बन्ध में ओद्योगिक (विकास तथा वित्तनम) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15 के अधीन एक जांच की गई, प्रबन्ध इस ठंग से किया जा रहा है जो सार्वजनिक हित में बहुत ही अहितकर है ;

अतः आव उपरोक्त अधिनियम की धारा 18-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार, राजकोट स्पर्धनग एण्ड बीविंग मिल्स, लि० राजकोट नामक उपरोक्त संपूर्ण अभिकारण का प्रबन्ध अपने अधिकार में लेने के लिये एतश्वारा गुजरात राज्य कपड़ा निगम लि० (गुजरात स्टेट ऐवन्टाइल कारपोरेशन), अहमदाबाद (एतवोपरान्त जो प्राधिकृत नियंत्रक कहा जावेगा) को प्राविहित करती है ; जिसकी शर्ते निम्नोक्त हैं, अर्थात् :—

- (1) प्राधिकृत नियंत्रक, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये निदेशों का पालन करेगा ;
 - (2) प्राधिकृत नियंत्रक इस आदेश के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि के लिए कार्यभार संभाले । केन्द्रीय सरकार यदि आवश्यक समझेगी, तो इससे पूर्व भी इस प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति को रद्द कर सकती है ।
2. यह आदेश सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशित होने की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि के निये प्रभावी रहेगा ।

[सं० फा० १(8)/लीक० पोल०/68.]

फार० सी० सेठी, अवर सचिव ।